प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन में भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

पूरा नाम -ज्योति सिंह राणा
विश्वविद्यालय का नाम - श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, उत्तर प्रदेश
गाइड का नाम - डॉ. ममता रानी

सारांश
वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की भूमिका केवल शिक्षण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह विद्यालयी प्रशासन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सामुदायिक समन्वय तथा डिजिटल प्रशासन का भी महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन में भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन द्वारा 800 शिक्षकों का चयन किया गया। आंकड़ों के संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित भूमिका मापनी का उपयोग किया गया तथा उनका विश्लेषण माध्य, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण द्वारा किया गया। अध्ययन में सरकारी एवं गैर-सरकारी तथा महिला एवं पुरुष शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में सार्थक अंतर पाया गया, जबकि हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के मध्य कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही यह स्पष्ट हुआ कि विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं डिजिटल प्रशासन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि बढ़ता प्रशासनिक कार्यभार उसके शैक्षणिक दायित्वों को भी प्रभावित करता है। अध्ययन यह स्थापित करता है कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक केवल ज्ञान का संप्रेषक नहीं, बल्कि शैक्षिक प्रशासन का केंद्रीय स्तंभ है। यह अध्ययन शैक्षिक नीति-निर्माताओं, विद्यालय प्रशासकों तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है।
प्रमुख शब्द: प्राथमिक विद्यालय, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन, प्रशासनिक भूमिका, प्राथमिक शिक्षा।

1. परिचय

प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। बालक के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक विकास की नींव इसी स्तर पर रखी जाती है, जिसके आधार पर उसके भावी शैक्षिक एवं व्यावसायिक जीवन का निर्माण होता है। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा न केवल साक्षरता के विस्तार का माध्यम है, बल्कि सामाजिक समानता, मानव संसाधन विकास तथा सतत राष्ट्रीय प्रगति का भी प्रमुख आधार है। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) जैसे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इन उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका अत्यंत केंद्रीय मानी जाती है, क्योंकि विद्यालय स्तर पर शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का वास्तविक क्रियान्वयन शिक्षक के माध्यम से ही संभव होता है।

पारंपरिक रूप से शिक्षक की भूमिका को ज्ञान के संप्रेषण, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के संचालन तक सीमित माना जाता था, किंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में यह अवधारणा व्यापक रूप से परिवर्तित हुई है। आज शिक्षक केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालय प्रबंधन, प्रशासनिक नियोजन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सतत मूल्यांकन, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ

समन्वय तथा डिजिटल प्रशासन जैसी अनेक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहा है। परिणामस्वरूप शिक्षक की भूमिका एक शैक्षणिक कार्यकर्ता से आगे बढ़कर विद्यालयी प्रशासन के सक्रिय सहभागी के रूप में विकसित हुई है। शैक्षिक प्रशासन का आशय उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से विद्यालय के मानवीय, भौतिक एवं शैक्षणिक संसाधनों का समन्वित एवं प्रभावी प्रबंधन किया जाता है, ताकि पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रभावी शैक्षिक प्रशासन केवल प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह नेतृत्व, समन्वय, योजना निर्माण, संसाधन प्रबंधन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सहभागितापूर्ण निर्णय प्रक्रिया पर आधारित होता है। विद्यालय स्तर पर इन सभी प्रक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण क्रियान्वयनकर्ता शिक्षक ही होता है। इसलिए वर्तमान संदर्भ में शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका का अध्ययन शैक्षिक गुणवत्ता, विद्यालयी प्रभावशीलता तथा संस्थागत विकास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।

पिछले दो दशकों में शिक्षा व्यवस्था में अनेक संरचनात्मक एवं नीतिगत परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान तथा डिजिटल प्रशासन के विस्तार ने विद्यालयी प्रशासन की प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, अधिगम उपलब्धि, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, आधार-आधारित सत्यापन, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि तथा विभिन्न शैक्षिक पोर्टलों पर नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जैसे अनेक कार्य अब शिक्षक की दैनिक प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हिस्सा बन चुके हैं। इन परिवर्तनों ने जहाँ विद्यालयी प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यभार में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बढ़ते प्रशासनिक उत्तरदायित्व शिक्षक की भूमिका, कार्यकुशलता तथा विद्यालयी प्रशासन की प्रभावशीलता को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं।

इस विषय पर उपलब्ध पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका शिक्षा व्यवस्था के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रामचन्द्रन एवं सहयोगियों ने भारतीय शिक्षकों की प्रेरणा एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के मध्य संबंध को रेखांकित करते हुए बताया कि बढ़ते प्रशासनिक कार्य शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि एवं शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। गोविन्दा एवं बंद्योपाध्याय ने स्थानीय शासन एवं सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में यह प्रतिपादित किया कि शिक्षक विद्यालय और समुदाय के मध्य एक प्रभावी समन्वयक के रूप में कार्य करता है। मेहरोत्रा ने प्राथमिक शिक्षा सुधारों के परिणामस्वरूप शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका के विस्तार को स्पष्ट किया, जबकि होय एवं मिस्केल ने विद्यालय को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखते हुए शिक्षक को प्रशासनिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना है। इसी प्रकार इंगरसोल, काइरियाकू, सेल्विन तथा यूनेस्को के अध्ययनों ने प्रशासनिक कार्यभार, डिजिटल प्रशासन, संगठनात्मक वातावरण तथा शिक्षक की कार्यकुशलता के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं।

यद्यपि उपलब्ध साहित्य शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालता है, तथापि प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में भारतीय परिस्थितियों पर आधारित क्षेत्रीय अनुभवजन्य अध्ययनों की संख्या अभी भी सीमित है। विशेष रूप से सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों, महिला एवं पुरुष शिक्षकों तथा विभिन्न शिक्षण माध्यमों के संदर्भ में प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। साथ ही विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता एवं डिजिटल प्रशासन जैसे प्रशासनिक आयामों का समेकित अध्ययन भी सीमित रूप में दृष्टिगत होता है। यही शोध-अंतर प्रस्तुत अध्ययन की आधारभूमि प्रदान करता है। इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन संबंधी भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। अध्ययन का उद्देश्य शिक्षक की प्रशासनिक सहभागिता के स्वरूप, विभिन्न प्रशासनिक आयामों में उसकी भूमिका तथा व्यक्तिगत एवं संस्थागत कारकों के आधार पर विद्यमान अंतरों का परीक्षण करना है। यह अध्ययन न केवल शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान का विस्तार करेगा, बल्कि शिक्षा नीति-निर्माताओं, विद्यालय प्रशासकों तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं

शिक्षक-केंद्रित सुधारों के लिए उपयोगी आधार प्रदान करेगा।

2. संबंधित साहित्य की समीक्षा

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यालयी प्रशासन की प्रभावशीलता का शिक्षक की भूमिका से गहरा संबंध है। समय के साथ शिक्षक की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में वह केवल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का संचालक न होकर विद्यालयी प्रशासन का भी एक प्रमुख अभिकर्ता बन गया है। विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल प्रशासन जैसे विविध आयामों में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी को समझने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। प्रस्तुत अध्ययन की सैद्धांतिक एवं अनुभवजन्य पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए प्रमुख अध्ययनों की समीक्षा निम्नवत प्रस्तुत की जा रही है।

भारतीय संदर्भ में रामचन्द्रन एवं सहयोगियों (2005) ने भारतीय शिक्षकों की अभिप्रेरणा, कार्य-परिस्थितियों तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि शिक्षकों पर बढ़ते प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक दायित्व उनके कार्य-संतोष तथा व्यावसायिक प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। अध्ययन में विशेष रूप से यह प्रतिपादित किया गया कि प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को शिक्षण के साथ-साथ अनेक प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, जिसके कारण उनके शैक्षणिक कार्य के लिए उपलब्ध समय प्रभावित होता है। यह अध्ययन इस तथ्य को स्थापित करता है कि प्रशासनिक कार्यभार एवं शिक्षण की गुणवत्ता के मध्य घनिष्ठ संबंध विद्यमान है।

मेहरोत्रा (2006) ने भारत में प्राथमिक शिक्षा सुधारों का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के विस्तार ने शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका को अधिक व्यापक बना दिया है। उनके अनुसार शिक्षक अब केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह शैक्षिक नीतियों एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमुख माध्यम भी है। अध्ययन यह इंगित करता है कि विद्यालय स्तर पर किसी भी शैक्षिक सुधार की सफलता काफी हद तक शिक्षक की प्रशासनिक दक्षता एवं उत्तरदायित्वबोध पर निर्भर करती है।

किंगडन (2007) ने भारतीय विद्यालयी शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि विद्यालयी प्रशासन की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता तथा संगठनात्मक संरचना शिक्षकों के कार्य-निष्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रशासनिक बाधाएँ एवं संसाधनों की असमानता शिक्षकों की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं, जिससे विद्यालय की समग्र कार्यकुशलता तथा विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम भी प्रभावित होते हैं।

गोविन्दा एवं बंद्योपाध्याय (2010) ने स्थानीय शासन व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासनिक स्वरूप का अध्ययन किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि विकेंद्रीकृत शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका केवल प्रशासनिक निर्देशों के पालन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह विद्यालय, अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय के मध्य एक सक्रिय समन्वयक के रूप में कार्य करता है। अध्ययन ने विद्यालय प्रबंधन समिति तथा सामुदायिक सहयोग को विद्यालयी प्रशासन की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक तत्व माना है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रतिवेदनों में विद्यालयी प्रशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्राथमिक शिक्षा के संचालन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इन प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी इंगित किया गया है कि बढ़ती प्रशासनिक अपेक्षाएँ, अभिलेखीय कार्य तथा विभिन्न योजनाओं के संचालन ने शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का दायरा पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत कर दिया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT, 2016) ने विद्यालयी गुणवत्ता सुधार एवं अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। परिषद ने स्पष्ट किया कि प्रभावी विद्यालयी प्रशासन तभी

संभव है जब शिक्षक प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, शैक्षणिक नेतृत्व तथा संस्थागत विकास में सक्रिय सहभागिता निभाए। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि विद्यालय की गुणवत्ता केवल भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि शिक्षक की प्रशासनिक दक्षता एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर भी समान रूप से आधारित होती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होय एवं मिस्केल (2013) ने विद्यालय को एक सामाजिक संगठन के रूप में व्याख्यायित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि प्रभावी शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके अनुसार विद्यालयी प्रशासन केवल नियंत्रण एवं निरीक्षण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व, सहयोग, समन्वय तथा सहभागितापूर्ण निर्णय-निर्माण पर आधारित एक गतिशील व्यवस्था है, जिसमें शिक्षक संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रमुख आधार होता है।

बुश (2011) ने शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि विद्यालयी प्रशासन की प्रभावशीलता शिक्षक की सक्रिय सहभागिता एवं नेतृत्व क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। उन्होंने सहभागी नेतृत्व, विकेंद्रीकृत प्रशासन तथा उत्तरदायित्व आधारित प्रबंधन को आधुनिक विद्यालय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ माना है।

इंगरसोल (2003) ने शिक्षक कार्यबल एवं संगठनात्मक संरचना का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक कार्यभार, संगठनात्मक वातावरण तथा कार्य-परिस्थितियाँ शिक्षक की व्यावसायिक संतुष्टि एवं कार्य-निरंतरता को प्रभावित करती हैं। अध्ययन के अनुसार अत्यधिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व शिक्षकों में कार्य-दबाव उत्पन्न कर सकते हैं तथा इससे विद्यालयी प्रभावशीलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

काइरियाकू (2001) ने शिक्षक तनाव के कारणों का विश्लेषण करते हुए प्रशासनिक कार्यभार, समय की कमी एवं निरंतर उत्तरदायित्व को शिक्षक तनाव के प्रमुख कारणों में सम्मिलित किया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि जब प्रशासनिक अपेक्षाएँ शिक्षण उत्तरदायित्वों पर अधिक प्रभाव डालती हैं, तब शिक्षकों की सृजनात्मकता एवं शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

सेल्विन (2016) ने शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि डिजिटल प्रशासन ने शिक्षक की भूमिका को और अधिक जटिल एवं बहुआयामी बना दिया है। ऑनलाइन अभिलेख प्रबंधन, डिजिटल रिपोर्टिंग तथा सूचना प्रबंधन की नई व्यवस्थाओं ने शिक्षक के प्रशासनिक दायित्वों में वृद्धि की है। यद्यपि इन प्रक्रियाओं ने प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ किया है, तथापि उन्होंने शिक्षकों से नई तकनीकी दक्षताओं की भी अपेक्षा की है।

यूनेस्को (2020) की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा की उपलब्धि में शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार बदलते शैक्षिक परिवेश में शिक्षक की भूमिका शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रशासनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक उत्तरदायित्व के प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करता है। रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि शिक्षक को पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग, व्यावसायिक विकास एवं संसाधन उपलब्ध कराए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका को शैक्षिक प्रशासन की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है। अधिकांश अध्ययनों ने प्रशासनिक उत्तरदायित्व, विद्यालय प्रबंधन, संगठनात्मक नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता एवं डिजिटल प्रशासन के महत्व को स्वीकार किया है। तथापि उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में भारतीय परिस्थितियों पर आधारित ऐसे अनुभवजन्य अध्ययन अपेक्षाकृत कम हैं, जिनमें सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों, महिला एवं पुरुष शिक्षकों तथा विभिन्न शिक्षण माध्यमों के आधार पर शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया हो। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता एवं डिजिटल प्रशासन जैसे प्रशासनिक आयामों का एकीकृत अध्ययन भी सीमित रूप से उपलब्ध है। इन्हीं

शोध-अंतरालों की पूर्ति के उद्देश्य से प्रस्तुत अध्ययन संचालित किया गया है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन संबंधी भूमिका का समग्र एवं अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके।

अध्ययन के उद्देश्य

1. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन में भूमिका का अध्ययन करना।
2. सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन संबंधी भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
3. महिला एवं पुरुष प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन में भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन संबंधी भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
5. विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण करना।

4. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन में भूमिका का विश्लेषण करने के लिए **वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि** (Descriptive Survey Method) का प्रयोग किया गया। यह विधि वर्तमान परिस्थितियों, व्यवहारों एवं प्रवृत्तियों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने तथा विभिन्न समूहों के मध्य विद्यमान समानताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद तक सीमित रखा गया, जहाँ सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अध्ययन की जनसंख्या के रूप में निर्धारित किया गया। अध्ययन के लिए **800 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों** का चयन किया गया। न्यादर्श चयन हेतु **स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन (Stratified Random Sampling)** विधि का उपयोग किया गया, जिससे विभिन्न उपसमूहों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। न्यादर्श में सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ महिला एवं पुरुष शिक्षकों को समान अनुपात में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग से 200 शिक्षकों का चयन किया गया तथा कुल 800 शिक्षकों का प्रतिनिधि न्यादर्श अध्ययन के लिए प्राप्त हुआ।

आंकड़ों के संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा **'शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन में भूमिका मापनी'** का निर्माण किया गया। मापनी का विकास संबंधित साहित्य, शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख आयामों तथा विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर किया गया। प्रारंभिक स्तर पर 40 कथनों का निर्माण किया गया, जिन्हें विषय विशेषज्ञों एवं शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी विद्वानों द्वारा परीक्षण एवं परिमार्जन के उपरांत अंतिम रूप दिया गया। विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर अस्पष्ट एवं पुनरावृत्त कथनों को हटाते हुए 30 कथनों को अंतिम मापनी में सम्मिलित किया गया। मापनी में विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल प्रशासन से संबंधित प्रमुख आयामों को समाहित किया गया। उपकरण की **विषय-वस्तु वैधता (Content Validity)** सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक प्रशासन एवं अनुसंधान पद्धति के विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया गया। विशेषज्ञों द्वारा कथनों की भाषा, प्रासंगिकता एवं स्पष्टता के आधार पर आवश्यक संशोधन किए गए। उपकरण की **विश्वसनीयता (Reliability)** का परीक्षण पायलट अध्ययन के माध्यम से किया गया, जिसके परिणामों ने यह संकेत दिया कि मापनी अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त रूप से विश्वसनीय एवं उपयोगी है। संकलित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण

माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation) तथा स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण (Independent Sample t-test) के माध्यम से किया गया। माध्य एवं मानक विचलन का उपयोग शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका की केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रसरण को समझने के लिए किया गया, जबकि टी-परीक्षण के माध्यम से सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों, महिला एवं पुरुष शिक्षकों तथा हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के शिक्षकों के मध्य प्रशासनिक भूमिका में विद्यमान अंतरों की सांख्यिकीय सार्थकता का परीक्षण किया गया। इस प्रकार प्रयुक्त अनुसंधान पद्धति एवं सांख्यिकीय तकनीकों ने अध्ययन के उद्देश्यों की वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ पूर्ति सुनिश्चित की।

5. परिणाम एवं विश्लेषण

5.1 शैक्षिक प्रशासन में शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका के आयामों का विश्लेषण

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन संबंधी भूमिका का समग्र विश्लेषण करने के उद्देश्य से प्रशासनिक भूमिका को छह प्रमुख आयामों—विद्यालय प्रबंधन एवं संगठनात्मक उत्तरदायित्व, अभिलेख संधारण एवं दस्तावेजीकरण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता, डिजिटल प्रशासन तथा प्रशासनिक कार्यभार—के आधार पर वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक आयाम का माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation) तथा प्राथमिकता क्रम (Rank) निर्धारित किया गया, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि शिक्षक किन प्रशासनिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

तालिका 5.1: शैक्षिक प्रशासन में शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका के विभिन्न आयामों का वर्णनात्मक विश्लेषण (N = 800)

क्रमांक	प्रशासनिक भूमिका का आयाम	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	क्रम (Rank)
1	विद्यालय प्रबंधन एवं संगठनात्मक उत्तरदायित्व	4.42	0.51	I
2	अभिलेख संधारण एवं दस्तावेजीकरण	4.36	0.57	II
3	शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन	4.28	0.60	III
4	सामुदायिक सहभागिता	4.15	0.64	IV
5	डिजिटल प्रशासन	4.08	0.69	V
6	प्रशासनिक कार्यभार एवं चुनौतियाँ	3.94	0.73	VI

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक विद्यालय प्रबंधन एवं संगठनात्मक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यों में सर्वाधिक सक्रिय पाए गए, जिसका माध्य 4.42 प्राप्त हुआ। यह इंगित करता है कि विद्यालय की दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों, समयबद्ध कार्य निष्पादन, अनुशासन, समन्वय तथा संगठनात्मक व्यवस्थाओं में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आयाम का मानक विचलन अपेक्षाकृत कम (0.51) होने से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं में पर्याप्त समानता विद्यमान है। अभिलेख संधारण एवं दस्तावेजीकरण का माध्य 4.36 प्राप्त हुआ, जो द्वितीय स्थान पर रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेखों, उपस्थिति पंजिका, प्रगति विवरण, विभागीय प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रशासनिक अभिलेखों के संधारण में शिक्षक नियमित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निष्कर्ष वर्तमान विद्यालयी प्रशासन में अभिलेखीय उत्तरदायित्वों के बढ़ते

महत्व को भी रेखांकित करता है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्य 4.28 प्राप्त हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न शैक्षिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, नामांकन अभियान, विद्यालय गुणवत्ता कार्यक्रम तथा अन्य शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में शिक्षक प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। सामुदायिक सहभागिता के आयाम का माध्य 4.15 प्राप्त हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यद्यपि यह आयाम प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, फिर भी इसकी प्राथमिकता विद्यालय प्रबंधन एवं अभिलेखीय कार्यों की अपेक्षा अपेक्षाकृत कम पाई गई।

डिजिटल प्रशासन का माध्य 4.08 प्राप्त हुआ, जो यह दर्शाता है कि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अभिलेख प्रबंधन, डिजिटल प्रतिवेदन, शैक्षिक पोर्टलों पर सूचना अद्यतन तथा अन्य तकनीकी प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जा रहा है। तथापि इस आयाम का अपेक्षाकृत अधिक मानक विचलन यह संकेत देता है कि शिक्षकों में डिजिटल दक्षता एवं संसाधनों की उपलब्धता के स्तर में कुछ भिन्नता विद्यमान है। प्रशासनिक कार्यभार एवं चुनौतियों का माध्य 3.94 प्राप्त हुआ, जो अन्य आयामों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। इसका आशय यह नहीं है कि इस आयाम का महत्व कम है, बल्कि यह दर्शाता है कि अधिकांश शिक्षकों ने प्रशासनिक कार्यभार को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में अनुभव किया। विभिन्न अभिलेखीय कार्यों, डिजिटल रिपोर्टिंग, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा गैर-शैक्षणिक उत्तरदायित्वों के कारण शिक्षकों के नियमित शिक्षण कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है।

5.2 सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

सरकारी एवं निजी (गैर-सरकारी) प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन संबंधी भूमिका में अंतर का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण (Independent Sample t-test) का प्रयोग किया गया। इसके परिणाम तालिका 5.2 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.2: सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

समूह	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t-मूल्य	सार्थकता
सरकारी विद्यालय	400	69.20	3.86	5.09	$p < 0.05$
निजी विद्यालय	400	64.40	4.61		

तालिका 5.2 के अनुसार सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का औसत प्रशासनिक भूमिका स्कोर (M = 69.20, SD = 3.86) निजी विद्यालयों के शिक्षकों (M = 64.40, SD = 4.61) की तुलना में अधिक प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त **t = 5.09** का मान 0.05 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में वास्तविक एवं महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है।

यह निष्कर्ष इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, अभिलेख संधारण, प्रशासनिक प्रतिवेदन, विद्यालय प्रबंधन तथा विभागीय उत्तरदायित्वों में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत निजी विद्यालयों में शिक्षकों का प्रमुख ध्यान शिक्षण एवं अधिगम गतिविधियों पर केंद्रित रहता है, जिसके कारण उनके प्रशासनिक दायित्वों का स्वरूप अपेक्षाकृत सीमित पाया गया। अतः प्रथम शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है तथा यह निष्कर्ष स्वीकार किया जाता है कि सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक अंतर विद्यमान है।

5.3 महिला एवं पुरुष शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

महिला एवं पुरुष शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में अंतर का परीक्षण स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण के माध्यम से किया गया। इसके परिणाम तालिका 5.3 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.3: महिला एवं पुरुष शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

समूह	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t-मूल्य	सार्थकता
महिला शिक्षक	400	68.07	5.19	4.19	$p < 0.05$
पुरुष शिक्षक	400	66.77	4.81		

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि महिला शिक्षकों का औसत प्रशासनिक भूमिका स्कोर (M = 68.07, SD = 5.19) पुरुष शिक्षकों (M = 66.77, SD = 4.81) से अधिक प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त **t = 4.19** का मान 0.05 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाया गया। यह परिणाम इंगित करता है कि महिला शिक्षक विद्यालयी प्रशासन, अभिलेखीय कार्य, विद्यार्थियों के समन्वय, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा संगठनात्मक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं। यद्यपि दोनों समूह प्रशासनिक कार्यों में सहभागी हैं, तथापि महिला शिक्षकों की प्रशासनिक सहभागिता का स्तर तुलनात्मक रूप से अधिक पाया गया। इसलिए द्वितीय शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है तथा यह निष्कर्ष स्वीकार किया जाता है कि महिला एवं पुरुष शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक अंतर विद्यमान है।

5.4 हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में अंतर का परीक्षण स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण द्वारा किया गया। परिणाम तालिका 5.4 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.4: हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

समूह	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t-मूल्य	सार्थकता
हिंदी माध्यम	400	66.10	4.81	1.30	$p > 0.05$
अंग्रेजी माध्यम	400	67.10	4.88		

तालिका 5.4 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के शिक्षकों का औसत प्रशासनिक भूमिका स्कोर (M = 67.10) हिंदी माध्यम के शिक्षकों (M = 66.10) की अपेक्षा थोड़ा अधिक प्राप्त हुआ, किंतु दोनों समूहों के मध्य यह अंतर अत्यंत सीमित है। प्राप्त **t = 1.30** का मान 0.05 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं पाया गया। यह परिणाम स्पष्ट करता है कि विद्यालय का शिक्षण माध्यम शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता। दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों को अभिलेख संधारण, प्रशासनिक प्रतिवेदन, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विद्यालय प्रबंधन जैसे समान प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः तृतीय

शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

6. चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन में भूमिका का विश्लेषण करना तथा विभिन्न संस्थागत एवं व्यक्तिगत कारकों के संदर्भ में उनकी प्रशासनिक सहभागिता का परीक्षण करना था। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका केवल शिक्षण-अधिगम तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विद्यालयी प्रशासन के विविध आयामों—जैसे विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता एवं डिजिटल प्रशासन—में भी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। यह निष्कर्ष आधुनिक विद्यालयी प्रशासन की उस अवधारणा का समर्थन करता है, जिसमें शिक्षक को प्रशासनिक व्यवस्था का सक्रिय एवं उत्तरदायी सहभागी माना गया है।

अध्ययन में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का औसत प्रशासनिक भूमिका स्कोर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सरकारी विद्यालयों में शासकीय योजनाओं, अभिलेखीय प्रक्रियाओं एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन संबंधी उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। यह परिणाम रामचन्द्रन एवं सहयोगियों (2005) तथा मेहरोत्रा (2006) के निष्कर्षों से सामंजस्य स्थापित करता है, जिन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि भारत में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशासनिक दायित्वों का विस्तार शिक्षा सुधार कार्यक्रमों एवं सरकारी योजनाओं के कारण निरंतर बढ़ा है। इसी प्रकार किंगडन (2007) द्वारा विद्यालयी प्रशासन एवं संसाधनों के प्रभाव पर व्यक्त विचार भी इस अध्ययन के निष्कर्षों का समर्थन करते हैं।

महिला एवं पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षकों की प्रशासनिक सहभागिता अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त हुई। यह परिणाम संकेत करता है कि महिला शिक्षक विद्यालयी संगठन, अभिलेखीय व्यवस्था, विद्यार्थियों के समन्वय तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय सक्रियता प्रदर्शित करती हैं। यद्यपि पूर्ववर्ती अध्ययनों में लिंग आधारित प्रशासनिक भूमिका पर सीमित शोध उपलब्ध हैं, तथापि यह निष्कर्ष विद्यालयी प्रशासन में महिला शिक्षकों की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करता है तथा इस क्षेत्र में आगे के अनुसंधान की आवश्यकता की ओर भी संकेत करता है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का शिक्षण माध्यम प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता। दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, अभिलेख संधारण, विभागीय प्रतिवेदन तथा विद्यालय प्रबंधन से संबंधित समान प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। यह परिणाम इस तथ्य को पुष्ट करता है कि प्रशासनिक भूमिका का निर्धारण विद्यालय के माध्यम की अपेक्षा प्रशासनिक संरचना एवं नीतिगत आवश्यकताओं से अधिक प्रभावित होता है।

प्रशासनिक भूमिका के विभिन्न आयामों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि विद्यालय प्रबंधन एवं संगठनात्मक उत्तरदायित्व, अभिलेख संधारण तथा शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन शिक्षकों की प्रमुख प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं। दूसरी ओर डिजिटल प्रशासन एवं प्रशासनिक कार्यभार आधुनिक विद्यालयी प्रशासन की उभरती हुई चुनौतियों के रूप में सामने आए। यह निष्कर्ष होय एवं मिस्केल (2013) के संगठनात्मक सिद्धांत, बुश (2011) के शैक्षिक नेतृत्व मॉडल, इंगरसोल (2003) के शिक्षक कार्यभार संबंधी अध्ययन, काइरियाकू (2001) के शिक्षक तनाव संबंधी निष्कर्ष तथा सेल्विन (2016) द्वारा प्रतिपादित डिजिटल प्रशासन की अवधारणा से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करता है। साथ ही यूनेस्को (2020) की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में शिक्षक की बहुआयामी प्रशासनिक भूमिका पर दिया गया विशेष बल भी प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों की पुष्टि करता है। समग्र रूप से यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्राथमिक विद्यालयों

के शिक्षक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत समन्वय तथा शैक्षिक उत्तरदायित्व के प्रमुख आधार हैं। इसलिए विद्यालयी प्रशासन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की प्रशासनिक भूमिका को नीतिगत, संगठनात्मक एवं व्यावसायिक स्तर पर पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाना आवश्यक है।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भूमिका शिक्षण तक सीमित न रहकर विद्यालयी प्रशासन के प्रत्येक महत्वपूर्ण आयाम तक विस्तृत हो चुकी है। विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल प्रशासन में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी विद्यालय की प्रशासनिक दक्षता एवं शैक्षिक गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन में सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा महिला एवं पुरुष शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ, जबकि हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की प्रशासनिक भूमिका में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। यह निष्कर्ष स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व मुख्यतः संस्थागत व्यवस्था एवं नीतिगत अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं, न कि केवल शिक्षण माध्यम से। अतः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक केवल ज्ञान का संप्रेषक नहीं, बल्कि शैक्षिक प्रशासन का केंद्रीय स्तंभ है, जिसकी प्रशासनिक दक्षता विद्यालय की समग्र प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण निर्धारक है।

8. शैक्षिक निहितार्थ

अध्ययन के निष्कर्ष शिक्षा प्रशासकों, नीति-निर्माताओं एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। शिक्षकों की बढ़ती प्रशासनिक भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि उन्हें विद्यालय प्रबंधन, अभिलेखीय व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन तथा नेतृत्व कौशल से संबंधित नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रशासनिक कार्यों का युक्तिसंगत वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिक्षकों के मूल शैक्षणिक दायित्व प्रभावित न हों। विद्यालयों में डिजिटल प्रशासन को सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं संसाधन-संपन्न बनाया जाना चाहिए तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सहयोगात्मक एवं सहभागी स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग को ऐसी नीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो शिक्षकों के अनावश्यक प्रशासनिक कार्यभार को कम करते हुए उनकी व्यावसायिक दक्षता एवं शैक्षणिक प्रभावशीलता को सुदृढ़ करें। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक-केंद्रित प्रशासनिक सुधारों के लिए उपयोगी आधार प्रदान करते हैं तथा भविष्य में विद्यालयी प्रशासन को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अग्रवाल, जे. सी. (2006). *आधुनिक शिक्षा का विकास एवं नियोजन.* नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।

बेस्ट, जॉन डब्ल्यू., एवं कान, जेम्स वी. (2006). *शिक्षा में अनुसंधान* (10वाँ संस्करण). नई दिल्ली: पियर्सन एजुकेशन।

बुश, टोनी. (2011). *शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन के सिद्धांत* (चौथा संस्करण). लंदन: सेज पब्लिकेशन्स।

कोहेन, एल., मैनियन, एल., एवं मॉरिसन, के. (2018). *शिक्षा में अनुसंधान की विधियाँ* (8वाँ संस्करण). लंदन: रूटलेज।

क्रेसवेल, जॉन डब्ल्यू. (2012). *शैक्षिक अनुसंधान: योजना, संचालन एवं मूल्यांकन* (4था संस्करण). बोस्टन: पियर्सन एजुकेशन।

गोविन्दा, आर. (सम्पा.). (2002). *भारत शिक्षा प्रतिवेदन: प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

गोविन्दा, आर., एवं बंद्योपाध्याय, एम. (2010). *प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय शासन व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता का परिवर्तित स्वरूप.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय।

होय, वेन के., एवं मिस्केल, सेसिल जी. (2013). *शैक्षिक प्रशासन: सिद्धांत, अनुसंधान एवं व्यवहार* (9वाँ संस्करण).

न्यूयॉर्क: मैकग्रा-हिल।
इंगरसोल, रिचर्ड एम. (2003). *शिक्षकों के कार्य पर नियंत्रण: विद्यालयों में शक्ति एवं उत्तरदायित्व.* कैम्ब्रिज: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
कौल, एल. (2008). *शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली.* नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
केरलिंगर, फ्रेड एन., एवं ली, हॉवर्ड बी. (2008). *व्यवहारिक अनुसंधान की आधारशिला* (4था संस्करण). नई दिल्ली: सेंगेज लर्निंग।
किंगडन, जी. जी. (2007). भारत में विद्यालयी शिक्षा की प्रगति. *ऑक्सफोर्ड रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, 23*(2), 168–195।
काइरियाकू, क्रिस. (2001). शिक्षक तनाव: भावी अनुसंधान की दिशाएँ. *एजुकेशनल रिव्यू, 53*(1), 27–35।
मेहरोत्रा, संतोष. (2006). *भारत में प्राथमिक शिक्षा सुधार: विकल्पों का विश्लेषण.* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।
मोहन्ती, जे. (2005). *शैक्षिक प्रशासन, पर्यवेक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन.* नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।
मुखोपाध्याय, एम. (2010). *विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद. (2005). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005.* नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद. (2016). *प्राथमिक स्तर पर अधिगम निष्पत्तियाँ.* नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय. (2014). *भारत में प्रारंभिक शिक्षा: यू-डाइस फ्लैश सांख्यिकी प्रतिवेदन.* नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD). (2019). *शिक्षण एवं अधिगम अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण (TALIS) 2018 प्रतिवेदन.* पेरिस: OECD पब्लिशिंग।
रामचन्द्रन, वी., पाल, एम., जैन, एस., शेखर, एस., एवं शर्मा, जे. (2005). *भारत में शिक्षक अभिप्रेरणा.* नई दिल्ली: एजुकेशनल रिसोर्स यूनिट।
भारत सरकार. (2009). *बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009.* नई दिल्ली: भारत सरकार।
सेल्विन, नील. (2016). *शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी: प्रमुख मुद्दे एवं विमर्श* (द्वितीय संस्करण). लंदन: ब्लूम्सबरी एकेडमिक।
तिलक, जे. बी. जी. (2002). *शिक्षा एवं निर्धनता.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान।
यूनेस्को. (2020). *वैश्विक शिक्षा निगरानी प्रतिवेदन 2020: समावेशन एवं शिक्षा.* पेरिस: यूनेस्को।
यूनिसेफ. (2019). *प्रत्येक बालक सीखे: यूनिसेफ शिक्षा रणनीति (2019–2030).* न्यूयॉर्क: यूनिसेफ।
विश्व बैंक. (2018). *विश्व विकास प्रतिवेदन 2018: शिक्षा की प्रतिज्ञा को साकार करना.* वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020.* नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।